छावनी शहर (Cantonment Towns)

संदर्भ: केंद्र सरकार ने नगरपालिका कानूनों में एकरूपता लाने के लिए कुछ छावनी नागरिक क्षेत्रों को पड़ोसी राज्य की नगर पालिकाओं के साथ विलय करने की योजना बनाई है।

- **उद्देश्य**: छावनी और आसपास के राज्य के नगरपालिका क्षेत्रों के लिए नगरपालिका कानूनों में एकरूपता लाना।
- **योजना:** कुछ छावनियों के नागरिक क्षेत्रों के शुल्क निर्धारण और उन्हें पड़ोसी राज्यों की नगर पालिकाओं के साथ विलय करने पर विचार करना।
- **प्रक्रिया:** 58 छावनियों में नागरिक क्षेत्रों के विच्छेदन और विलय के तौर-तरीकों को फीडबैक के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ साझा किया गया है।
- **परामर्श**: विच्छेदन और विलय के लिए राज्य सरकारों का सक्रिय परामर्श और सहमति आवश्यक है।
- **समय-सीमा:** परामर्श की आवश्यकता के कारण कार्यान्वयन की समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है।
- **सार्वजनिक इनपुट:** जनता, निर्वाचित प्रतिनिधियों और कुछ राज्य सरकारों से इस विलय का समर्थन करने वाले अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।
- **राज्य सरकार की योजनाएं:** छावनी क्षेत्रों में राज्य सरकार की योजनाओं को लागू करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यहाँ के निवासियों को पहले से ही विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलता है।

छावनियाँ क्या हैं?

- **छावनी:** ये केंद्र सरकार द्वारा शासित, छावनी अधिनियम, 2006 के तहत घोषित क्षेत्र हैं।
- **श्रेणियाँ**: जनसंख्या के आधार पर इनकी चार श्रेणियाँ हैं - श्रेणी I (>50,000), श्रेणी II (10,000-50,000), श्रेणी III (2,500-10,000), और श्रेणी IV (<2,500)।
- **प्राधिकरण:** छावनी बोर्ड रक्षा मंत्रालय के अधीन है।
    - **संरचना**: इसमें 8 सदस्य होते हैं - 1 स्टेशन कमांडर, 3 पदेन सदस्य, 3 नामांकित सैन्य सदस्य और 1 जिला मजिस्ट्रेट का प्रतिनिधि।
    - **सेवाएँ**: ये स्वच्छता, प्राथमिक शिक्षा, सड़क, प्रकाश व्यवस्था, जल आपूर्ति, पुल रखरखाव और सार्वजनिक अस्पताल आदि से सम्बन्धित सेवाए प्रदान करती हैं।
- **छावनियाँ बनाम सैन्य स्टेशन**: छावनियों में नागरिक और सैन्य दोनों वर्ग के लोग उपस्थिति होते हैं , जबकि सैन्य स्टेशन पूरी तरह से सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों के लिए होते हैं।

हाइग्रोइलेक्ट्रिसिटी

संदर्भ: हाइग्रोइलेक्ट्रिसिटी, शोधकर्ताओं द्वारा आर्द्र हवा से बिजली उत्पन्न करने में सक्षम तकनीक विकसित की गई है।

तकनीक

- हाइग्रोइलेक्ट्रिसिटी हवा में नमी का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करती है।
- यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भविष्य में एक महत्वपूर्ण ऊर्जा योगदानकर्ता बनने की क्षमता रखता है।
- हाइग्रोइलेक्ट्रिसिटी का उपयोग एक छोटे उपकरण के माध्यम से किया जाता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड और एक नैनोपोर्स परत होती है।
- 100 नैनोमीटर से कम व्यास वाले नैनोपोर्स, हवा से पानी के अणुओं को उपकरण से गुजरने में सक्षम बनाते हैं।
- जैसे ही पानी के अणु ऊपरी कक्ष से निचले कक्ष की ओर बढ़ते हैं, वे नैनोपोर्स के किनारों पर विद्युत आवेश में असंतुलन उत्पन्न करते हैं।
- यह प्रक्रिया प्रभावी ढंग से उपकरण को एक लघु बैटरी में बदल देती है, जिससे निरंतर बिजली उत्पन्न होती है।
- जिस तरह तूफान के दौरान बादल विद्युत आवेश पैदा करते हैं, उसी तरह यह तकनीक हवा की नमी को उपयोग योग्य बिजली में परिवर्तित करती है।
- **लाभ**: सौर और पवन के विपरीत, हवा में नमी लगातार उपलब्ध रहती है, जो एक स्थायी ऊर्जा भंडार प्रदान करती है।
- **चुनौतियाँ**: वर्तमान उपकरण केवल थोड़ी मात्रा में बिजली का उत्पादन कर सकता है, और व्यावहारिक ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए स्केलिंग एक महत्वपूर्ण बाधा बनी हुई है।

इलेक्ट्रोड क्या हैं?

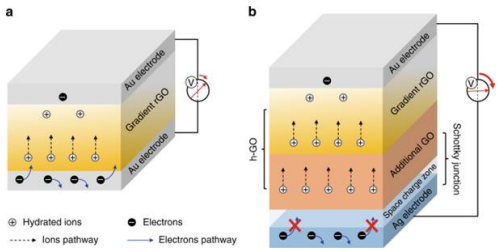

- इलेक्ट्रोड ठोस कंडक्टर होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत प्रवाहकीय समाधान या पिघले हुए नमक से बिजली के प्रवाह को सुविधाजनक बनाते हैं।
- ये बैटरी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसे अनुप्रयोगों में विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं।
- इलेक्ट्रोड के दो प्राथमिक प्रकार हैं: एनोड और कैथोड।
    - एनोड ऑक्सीकरण से गुजरता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, जबकि कैथोड में कमी आती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना शामिल होता है।
    - बैटरियों में, एनोड नकारात्मक टर्मिनल है, और कैथोड सकारात्मक टर्मिनल है।
    - किसी सर्किट से कनेक्ट होने पर, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर प्रवाहित होते हैं, जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है।

नैनोपोर्स क्या हैं?

- नैनोपोर्स बेहद छोटे छेद होते हैं, जिनका व्यास सामान्यतः कुछ नैनोमीटर होता है।
- ये जैविक कोशिकाओं, सिंथेटिक झिल्ली और ग्राफीन सहित विभिन्न सामग्रियों में पाए जाते हैं।

अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक 2023

संदर्भ: अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक 2023 को स्थायी संसदीय समिति से समर्थन प्राप्त हुआ है।

- अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक को मार्च 2023 को पेश किया गया था जिसे अध्यक्ष द्वारा रक्षा संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया था।
- यह विधयेक केंद्र सरकार को संयुक्त सेवा कमांड सहित अंतर-सेवा संगठन बनाने के लिए अधिकृत करता है।
- विधेयक इन संगठनों के प्रमुखों को कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन को सुनिश्चित करते हुए तीनों सेवाओं में से किसी एक के कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान करता है।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं:

- **अंतर-सेवा संगठन (आईएसओ):**
    - इसके पारित होने पर केंद्र सरकार एक संयुक्त सेवा कमान बना सकती है।
    - मौजूदा आईएसओ (ए एंड एन कमांड, डिफेंस स्पेस एजेंसी, एनडीए) को विधेयक के तहत गठित माना जाएगा।
- **आईएसओ का अधीक्षण और कमान/नियंत्रण:**
    - केंद्र सरकार आईएसओ पर अधीक्षण रखेगी।
    - आईएसओ के कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड के पास आईएसओ में सेवारत या उससे जुड़े कर्मियों पर कमांड और नियंत्रण होगा।
- **कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड के लिए पात्रता:**
    - थल सेना के जनरल ऑफिसर (ब्रिगेडियर रैंक से ऊपर)।
    - नौसेना के ध्वज अधिकारी (बेड़े के एडमिरल, एडमिरल, वाइस-एडमिरल, या रियर-एडमिरल का पद)।
    - वायु सेना के वायु अधिकारी (ग्रुप कैप्टन के पद से ऊपर)।
- **कमांडिंग आफिसर:**
    - यह किसी इकाई, जहाज या प्रतिष्ठान की कमान संभालता है और आईएसओ के कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करता है।

- इसे आईएसओ में नियुक्त, प्रतिनियुक्त, तैनात या संलग्न कर्मियों पर सभी अनुशासनात्मक या प्रशासनिक कार्रवाई शुरू करने का अधिकार होता है।

➢ **वर्तमान व्यवस्था में समस्याएँ**

- **वर्तमान प्रणाली**: आईएसओ में कार्मिक सेना, वायु सेना और नौसेना के अलग-अलग कानूनों द्वारा शासित होते हैं।
- **सीमाएं:** मौजूदा कानूनी ढांचा त्रि-सेवा मामलों में अन्य सेवाओं के सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक/प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए एक सेवा के अधिकारियों को प्रतिबंधित करता है।
- **उदाहरण:** संयुक्त कमान का नेतृत्व करने वाला तीन सितारा जनरल अपने अधीन वायु सेना या नौसेना कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता है।
- **परिणाम:** आईएसओ में कार्मिकों को अनुशासनात्मक/प्रशासनिक कार्रवाइयों के लिए अपनी मूल सेवा इकाइयों में लौटना होगा, जिससे उनकी गतिशीलता में विलंब होता है और इसका वित्तीय प्रभाव पड़ता है ।

पैनल की सिफ़ारिशें

➢ विधेयक को बिना किसी संशोधन के पारित करने और एक क़ानून के रूप में अधिनियमित करने का प्रस्ताव है, जिसका उद्देश्य आईएसओ में त्रि-सेवा एकीकरण और संयुक्त कौशल को बढ़ाना है।

➢ एक बार प्रभावी होने के बाद, कानून आईएसओ के कामकाज में सुधार लाएगा और उनके संचालन में स्वतंत्रता बढ़ेगी।

➢ मामलों के त्वरित समाधान को सक्षम करके यह बिल आईएसओ के भीतर अनुशासन के मानक पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा।

खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट

संदर्भ: हाल ही में, वर्ष 2023 के लिए खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट (जीआरएफसी) प्रकाशित की गई है।

रिपोर्ट के बारे में

➢ जीआरएफसी का प्रकाशन खाद्य संकट के खिलाफ वैश्विक नेटवर्क बनाने के लिए खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क द्वारा किया जाता है।

➢ यह रिपोर्ट देशों में तीव्र खाद्य असुरक्षा का आकलन करती है।

➢ रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा पर शहरीकरण के प्रभाव पर प्रकाश डालती है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

➢ **वैश्विक संकट और एसडीजी:** रिपोर्ट मूल्यांकन को प्रभावित करने वाली ऐतिहासिक घटनाओं को संबोधित करती है, जिसमें महामारी, आर्थिक संकट, युद्ध (यूक्रेन), और बढ़ती खाद्य कीमतें शामिल हैं।

➢ **शून्य भूख पर प्रगति:** विश्व स्तर पर भूख की समस्या अब घट रही है, लेकिन अभी भी पूर्व-कोविड स्तर से काफी ऊपर है, एसडीजी 2 (शून्य भूख) लक्ष्य से अभी भी बहुत दूर है।

➢ **2022 के लिए खाद्य असुरक्षा अनुभव स्केल (FIES) का अनुमान:** वैश्विक स्तर पर कोई प्रगति नहीं हुई है, मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा की व्यापकता दो वर्षों से अपरिवर्तित बनी हुई है।

➢ **अपर्याप्त भोजन :**2022 में 2.4 बिलियन लोगों को अपर्याप्त भोजन मिला है (2019 से 391 मिलियन अधिक)।

➢ **अल्पपोषण**: 2021 से 2022 तक अपेक्षाकृत अपरिवर्तित, 2022 में विश्व की लगभग 9.2% आबादी अल्पपोषण से प्रभावित होगी (2019 में 7.9%)।

➢ **संतुलित आहार का सेवन:** 2020 में लगभग 3.2 बिलियन लोगों को संतुलित आहार प्राप्त नही हुआ , जबकि 2021 में थोड़ा सुधार हुआ है।

- संतुलित आहार की वैश्विक लागत 2019 और 2021 के बीच 6.7% बढ़ गई।
- 2030 तक 600 मिलियन लोगों के लंबे समय तक अल्पपोषित होने का अनुमान है।

➢ **स्टंटिंग, वेस्टिंग और मोटापा: स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग में सकारात्मक रुझान:**

- स्टंटिंग 2000 में 204.2 मिलियन से घटकर 2022 में 148.1 मिलियन हो गई।
- बच्चों में वेस्टिंग की संख्या 2000 में 54.1 मिलियन से घटकर 2022 में 45 मिलियन हो गई।

- **अधिक वजन और मोटापा: बच्चों के अधिक वजन या मोटापे में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं:**
  - 2000 में 5.3% (33 मिलियन) से बढ़कर 2022 में 5.6% (37 मिलियन) हो गया।

वैश्विक संसदीय संधि

- **नई बहुपक्षीय संस्था:** वैश्विक संसद संधि में कृषि खाद्य प्रणाली में गरीबी, भूख और कुपोषण से निपटने के लिए एक बहुपक्षीय संस्था की स्थापना की गई है।
- **वैश्विक संसदीय शिखर सम्मेलन**: यह चिली में आयोजित की गई जिसमें , 64 देशों के सांसदों ने भाग लिया।
- **वैश्विक संसदीय समझौता:** शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित, सभी के लिए टिकाऊ और सुलभ भोजन सुनिश्चित करने के लिए कृषि खाद्य प्रणाली में सुधार करने की प्रतिबद्धता जताई गई।
- **संधि की विशेषताएं:**
  - **वित्तीय सहायता :** इसमें खाद्य समानता और बजटीय सहायता के लिए वैधानिक मसौदा तैयार करना शामिल है।
  - **उद्देश्य:** 2030 तक संयुक्त राष्ट्र के शून्य गरीबी, भूख और कुपोषण के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना।
  - **राजनीतिक समर्थन**: यह कृषि खाद्य प्रणाली सुधार नीतियों और समान खाद्य वितरण कानूनों का समर्थन करता है।
  - **प्रगति रिपोर्टिंग**: सांसद जवाबदेही के लिए प्रगति रिपोर्ट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
  - **विधायी प्रभाव:** 35 स्वीकृत कानूनों के परिणामस्वरूप, पारिवारिक खेती, जिम्मेदार कृषि निवेश, लैंगिक समानता और भोजन की हानि और बर्बादी को कवर किया गया।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

पीएम-डिवाइन योजना

संदर्भ: हाल ही में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रधान मंत्री विकास पहल (PM-DevINE) को 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में पेश किया गया था।

क्या है पीएम-डिवाइन योजना?

पीएम-डिवाइन योजना, जो "उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रधान मंत्री विकास पहल" संक्षिप्त रूप है, 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे केंद्रीय बजट 2022-23 में पेश किया गया है। इस योजना का लक्ष्य भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) में विकास को बढ़ावा देना है।

मंजूरी: कैबिनेट ने 12 अक्टूबर 2022 को PM-DevINE योजना को मंजूरी दे दी थी।

अवधि: इस योजना का परिव्यय 2022-23 से 2025-26 तक 4 साल की अवधि के लिए रु. 6,600 करोड़ है।

उद्देश्य: पीएम-डिवाइन का लक्ष्य बुनियादी ढांचे को वित्त पोषित करना, सामाजिक विकास परियोजनाओं का समर्थन करना, आजीविका गतिविधियों को सक्षम करना और उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) में विकास अंतराल को पाटना है।

परियोजनाएं: वित्त वर्ष 2022-23 में मंजूरी के लिए ग्यारह परियोजनाओं का चयन किया गया है, जिसमें प्रारंभिक आवंटन रु. 1500 करोड़ है।

पीएसएलवी-सी56 (PSLV-C56) मिशन

संदर्भ: इसरो 30 जुलाई को श्रीहरिकोटा से सिंगापुर के डीएस-एसएआर (DS-SAR) उपग्रह को ले जाने वाले PSLV-C56 मिशन को लॉन्च करने के लिए तैयार है।

PSLV-C56 क्या है?

PSLV-C56 का मतलब ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान-C56 है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा संचालित एक अंतरिक्ष मिशन है।

संरचना: PSLV-C56, PSLV-C55 के समान अपने कोर-अलोन मोड में है, और DS-SAR को 5 डिग्री झुकाव और 535 किमी की ऊंचाई पर निकट-भूमध्यरेखीय कक्षा (NEO) में लॉन्च करेगा।

डीएस-एसएआर उपग्रह: डीएस-एसएआर, डीएसटीए और एसटी इंजीनियरिंग के साथ विकसित, सिंगापुर की सरकारी एजेंसियों के लिए सैटेलाइट इमेजरी समर्थन और वाणिज्यिक ग्राहकों के लिए भू-स्थानिक सेवाएं प्रदान करता है।

सिंथेटिक एपर्चर रडार (एसएआर): डीएस-एसएआर इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (आईएआई) द्वारा विकसित एक एसएआर पेलोड रखता है जो पूर्ण पोलारिमेट्री पर 1 मीटर रिज़ॉल्यूशन पर इमेजिंग के साथ सभी मौसम में दिन और रात की कवरेज को सक्षम बनाता है।

सह-यात्री: PSLV-C56, DS-SAR और छह सह-यात्रियों को ले जाएगा- IoT कनेक्टिविटी के लिए VELOX-AM, ARCADE, SCOOB-II, गैलासिया-2, ORB-12 STRIDER और NuLIoN।

पेलोड: PSLV-C56 सात उपग्रहों को ले जायेगा, जिनमें सिंगापुर का 351.9 किलोग्राम का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह DS-SAR और तीन नैनो उपग्रह शामिल हैं।

मेरी माटी, मेरा देश

संदर्भ: हाल ही में, केंद्र सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में "मेरी माटी, मेरा देश" अभियान शुरू किया।

मेरी माटी, मेरा देश क्या है?

"मेरी माटी, मेरा देश" राष्ट्रीय गौरव और पर्यावरण चेतना को बढ़ावा देने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत एक सरकारी पहल है।

उद्यान विकास: अगस्त में देश के विभिन्न हिस्सों से एकत्र की गई मिट्टी का उपयोग दिल्ली में कर्तव्य पथ के किनारे एक उद्यान विकसित करने के लिए किया जाएगा।

कार्यक्रम स्तर: आयोजनों और कार्यक्रमों की योजना विभिन्न स्तरों पर बनाई जाती है - पंचायत, गाँव, ब्लॉक, शहरी स्थानीय निकाय और राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर।

समय सीमा: पंचायत स्तरीय कार्यक्रम 9 से 15 अगस्त के बीच आयोजित किए जाएंगे।

पांच सूत्री एजेंडा: अभियान के एजेंडे में शामिल हैं:

- सर्वोच्च बलिदान के लिए स्मारक पट्टिका।
- **वीरों का सम्मान:** स्वतंत्रता सेनानियों, रक्षा कर्मियों, सीएपीएफ और राज्य पुलिस।

फ्लोरीन

संदर्भ: 20 जुलाई, 2023 को ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों ने आवश्यक रासायनिक यौगिक उत्पादन के लिए फ्लोरीन परमाणु प्राप्त करने में एक बड़ी सफलता हासिल की।

फ्लोरीन क्या है?

फ्लोरीन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक (F) और परमाणु संख्या 9 है। यह सबसे हल्का हैलोजन तत्व है और सभी रासायनिक तत्वों में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है।

संभावित परिवर्तन: फ्लोरीन-आधारित यौगिक प्राप्त करने की नई विधि एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि है।

औद्योगिक उपयोग: प्लास्टिक, कृषि रसायन, बैटरी और फार्मास्यूटिकल्स में उपयोग किए जाने वाले फ्लोरोकेमिकल्स के निर्माण के लिए फ्लोरीन महत्वपूर्ण है।

विषाक्तता और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ: फ्लोरीन गैस और हाइड्रोजन फ्लोराइड के संपर्क में आना फेफड़ों, त्वचा और आँखों के लिए खतरनाक हो सकता है। फ्लोराइड से हड्डियों का क्षय, ऑस्टियोपोरोसिस, गठिया और मस्तिष्क क्षति हो सकती है।

प्राकृतिक उपलब्धता: फ्लोरीन, फ्लोरस्पार, क्रायोलाइट और फ्लोरापाटाइट जैसे खनिजों में रासायनिक यौगिकों में पाया जाता है।

पर्यावरणीय प्रभाव: सीएफसी जैसे फ्लोरीन युक्त यौगिकों को ओजोन परत संरक्षण के लिए नियंत्रित किया गया है, एचएफसी ने उन्हें औद्योगिक अनुप्रयोगों में प्रतिस्थापित कर दिया है।

कर्मचारी भविष्य - निधि संस्था

सन्दर्भ: हाल ही में, केंद्र ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की भविष्य निधि (पीएफ) में जमा पर ब्याज दर को बढ़ाकर 8.15% करने की सिफारिश को स्वीकार कर लिया।

कर्मचारी भविष्य - निधि संस्था: ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि और विविध अधिनियम, 1952 के तहत संचालित एक वैधानिक निकाय है।

प्रशासनिक नियंत्रण: यह केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन संचालित होता है।

केंद्रीय न्यासी बोर्ड: ईपीएफओ केंद्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा शासित होता है, जिसमें सरकार (केंद्र और राज्य), नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

योजनाएं: ईपीएफओ तीन योजनाओं का प्रबंधन करता है:

i. कर्मचारी भविष्य निधि योजना (ईपीएफ)
ii. कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) और
iii. कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (ईडीएलआई)।

पेंशन योजना (ईपीएस): यह संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रदान करती है, बशर्ते कि उन्होंने कम से कम 10 वर्षों तक सेवा की हो।

योगदान: नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ईपीएफ में प्रत्येक कर्मचारी के वेतन का 12% योगदान करते हैं, जिसमें नियोक्ता के योगदान का एक हिस्सा ईपीएस को आवंटित किया जाता है।

समाचार में स्थान

डेन्यूब नदी

सन्दर्भ: हाल ही में, रूसी सेना ने विस्फोटक ड्रोन का उपयोग करके दक्षिणी यूक्रेन में डेन्यूब नदी पर स्थित बंदरगाह के बुनियादी ढांचे पर हमला किया।

डेन्यूब नदी:

- यूरोप की प्रमुख नदियों में से एक, यह यूक्रेन सहित कई देशों से होकर बहती है।
- यह दक्षिणी यूक्रेन में यूक्रेन और रोमानिया के बीच सीमा का हिस्सा बनता है।
- यह नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है , जिसकी लंबाई लगभग 2,850 किलोमीटर है और यह काला सागर में गिरती है।
- डेन्यूब नदी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया, बुल्गारिया और रोमानिया सहित दस देशों से होकर गुजरती है।
- इसके तट पर स्थित प्रमुख शहरों में वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड और ब्रातिस्लावा शामिल हैं।
- रोमानिया और यूक्रेन में डेन्यूब डेल्टा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है।

महत्व: यूरोप के प्रमुख जलमार्गों में से एक, परिवहन, व्यापार और पर्यटन का समर्थन करता है।

डेन्यूब नदी पर बंदरगाह:

- वियना बंदरगाह, ऑस्ट्रिया: वियना में स्थित एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह।
- ब्रातिस्लावा बंदरगाह, स्लोवाकिया: व्यापार के लिए ब्रातिस्लावा में प्रमुख बंदरगाह।
- बुडापेस्ट, हंगरी का बंदरगाह: हंगरी को यूरोप से जोड़ता है।
- बेलग्रेड बंदरगाह, सर्बिया: व्यापार और यात्रियों के लिए रणनीतिक बंदरगाह।
- नोवी सैड, सर्बिया का बंदरगाह: कार्गो प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण बंदरगाह।
- रूस का बंदरगाह, बुल्गारिया: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण बंदरगाह।
- कॉन्स्टेंटा का बंदरगाह, रोमानिया: डेन्यूब के मुहाने पर काला सागर से जुड़ने वाला सबसे बड़ा बंदरगाह।